technology and seedlings for plantation in the arid and semi-arid regions of the country including Rajasthan;

(b) if so, the details therof; and

(c) what response Government have received from private sector in developing the Jojoba plantation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF WASTELANDS DEVELOPMENT) (COL. RAM SINGH): (a) and (b) The Department of Wastelands Development, in collaboration with the Government of Rajasthan have taken steps to take up pilot projects for plantation of Jojoba in Rajasthan. In this regard an Executive Programme was signed between the Department of Wastelands Development and the Government of Israel to promote cooperation between the two countries in Jojoba plantations including activities like research, education, extension, training, model plantations, etc. No specific proposal from Israel has yet been received for transferring technology and seedlings for Jojoba plantations. The Executive Programme was signed in March, 1995 and under it, it is expected that some proposals will be generated for transfer of technology and seedlings from Israel to the arid and semi-arid regions of the country, including Rajasthan.

(c) The Department of Wastelands Development had organised a Consultation on Jojoba at CAZRI, Jodhpur, on 14-10-1993 in which State Government officers, farmers and representatives of Research Institutions were present. Enquiries of a general nature for taking up Jojoba plantation have been made in the Department of Wastelands Development. However, the Government of Rajasthan have received good response from the private sector to take up Jojoba plantations.

जबलपुर, मध्य प्रदेश में विकास खंड

6516. **श्री शिवप्रसाद चनपुरिया:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के कौन-कौन से विकास खंड लिए गए हैं तथा वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी राशि जारी की गई है और राशि की सहायता से विकास खंड-वार कितनी नौकरियां सृजित की गई हैं;

(ख) जबलपुर जिले के कुंडम विकास खंड में सुनिश्चित रोजगार योजना के उद्देश्यों के अनुरूप अकुशल स्वरूप के शारीरिक श्रम हेतु जिन श्रमिकों को 100 (सौ) दिनों का सुनिश्चित रोजगार उक्त वर्षों में उपलब्ध कराया गया उनकी संख्या व नाम क्या हैं;

(ग) क्या इस योजना के नियमों के अन्तर्गत जिला और विकास खंड स्तर पर समितियां गठित की गई हैं, यदि हां, तो स्तर-वार उनके नाम क्या-क्या हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि जबलपुर जिले के जिला मास्टर प्लान में दर्शाए गए निर्माण कार्यों का निर्माण न करके कुछ अन्य कार्य किए गए, यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) और (ख) मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कवर किए गए खंडों के नाम और वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान खंडवार रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां विवरण में दर्शाई गई हैं (नीचे देखिए)। सृजित कार्यों की संख्या, श्रमिकों के नाम, जिनको सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया है, को भारत सरकार स्तर पर खंडवार नहीं रखा जाता है।

(ग) सुनिश्चित रोजगार योजना की मार्गदर्शिकाओं के अनुसार राज्य सरकार को प्रत्येक जिले, जहां योजना चल रही है, में जिला सुनिश्चित रोजगार समिति और सुनिश्चित रोजगार योजना द्वारा कवर किए गए प्रत्येक खंड में एक खंड सुनिश्चित रोजगार योजना समिति का गठन करना है। इन समितियों के गठन के ब्यौरे और उनके नाम भारत सरकार स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(घ) सरकार के ध्यान में यह बात नहीं आई है कि निर्माण कार्यों, जिनको जबलपुर जिले के जिला मास्टर प्लान में शामिल किया गया है, को सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत नहीं किया जा रहा था।

विवरण

क्रमांक	मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कवर किए गए खंडों के नाम	रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां	
		1993-94	1994-95
1.	कुंडम	55.00	40.00
2.	घिमेर खेडा	55.00	40.00
3.	हरवाम	55.00	40.00
4.	बधान	55.00	40.00
5.	रिथी	55.00	40.00
6.	बरोरी बंघ*	शून्य	30.00
7.	मझौली*	शून्य	30.00
8.	विजय राघवगढ़*	शून्य	30.00
9.	बरगी*	शून्य	30.00
10.	शाहपुर*	शून्य	30.00

*1994-95 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत शामिल।

मध्य प्रदेश में बंजर भूमि विकास कार्य

6517. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया:** क्या **प्रधानमंत्री** 23 मार्च, 1995 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1640, 1643 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में उन क्षेत्रों के नाम क्या-क्या हैं, जिनके लिए मध्य प्रदेश में बंजर भूमि विकास कार्यों में लगे हुए सरकारी तथा निजी अभिकरणों को बंजर भूमि विकास कार्य सौंपा गया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (परती भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह): विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के तहत बंजरभूमि सहित विभिन्न प्रकार की भूमि पर राज्य भर में वन रोपण/वृक्षारोपण 20-सूत्रीय कार्यक्रम के सूत्र संख्या 16 के तहत किया जाता है। इसमें समेकित बंजरभूमि विकास परियोजनाएं तथा राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड की अनुदान सहायता योजनाओं के तहत सरकार तथा स्वयंसेवी एजेंसियों द्वारा किया जाने वाला कार्य भी शामिल है। समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के तहत सरकारी एजेंसियां भोपाल, छिंदवाड़ा, धार, दुर्ग, इंदौर, झाबुआ, मांडला, रायगढ़, रायपुर, टीकमगढ़, सरगुजा तथा उज्जैन जिलों में बंजरभूमि के विकास के कार्यों में लगी है। इन योजनाओं के तहत स्वयंसेवी एजेंसियां और उनके संचलन के क्षेत्र नीचे दिये गये है।

क्रम सं॰	योजना का नाम	स्वयंसेवी एजेंसी का नाम	जिले का नाम
1.	समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	राष्ट्रीय मानव व्यवस्थापन तथा पर्यावरण केन्द्र	झाबुआ
2.	समेकित बंजरभूमि विकास परियोजनाएं	विकास विकल्प	दतिया
3.	अनुदान सहायता	राष्ट्रीय मानव व्यवस्थापन तथा पर्यावरण केन्द्र	भोपाल बेतूल और झाबुआ